साखारोव पुरस्कार 2026: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और उसके अधिकारी

अंतरराष्ट्रीय संबंध | समाचार संदर्भ: 22 अक्टूबर 2026 (यूरोपीय संसद प्रेस-विज्ञप्ति) | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

यूरोपीय संसद ने 22 अक्टूबर 2026 को विचार-स्वतंत्रता के लिए दिया जाने वाला साखारोव पुरस्कार 2026 संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और उसके अधिकारियों को घोषित किया। घोषणा संसद-अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला ने की; औपचारिक समारोह दिसंबर में स्ट्रासबर्ग (फ्रांस) में संसद के पूर्ण-सत्र के दौरान होगा।

पुरस्कार और ICC की पृष्ठभूमि

- 1988 में स्थापित यह पुरस्कार सोवियत भौतिकविद् और असंतुष्ट नेता आंद्रेई साखारोव के नाम पर है; यूरोपीय संसद हर साल मानवाधिकार, अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय कानून और लोकतंत्र के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को देती है।
- ICC रोम सन्तियमाला (Rome Statute — वह अंतरराष्ट्रीय संधि जिससे ICC बना) से शासित दुनिया की पहली स्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत है; यह नरसंहार, युद्ध-अपराध, मानवता-विरुद्ध अपराध और आक्रमण के अपराधों की जाँच व मुकदमा करती है। यह "अंतिम उपाय की अदालत" है — तब कदम बढ़ाती है जब राष्ट्रीय अदालतें कार्रवाई न करें या न कर सकें।
- विज्ञप्ति में 2025 से ICC और उसके अभियोजकों, न्यायाधीशों व कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंधों (विशेषकर अमेरिका द्वारा) का उल्लेख है और EU की 'अवरोधक संरचना' (blocking statute — विदेशी कानूनों का प्रभाव EU में रद्द करने वाला कानून) सक्रिय करने की माँग दोहराई गई है।

संदर्भ और विस्तृत व्याख्या

साखारोव पुरस्कार की प्रतिष्ठा इसके इतिहास से जुड़ी है। आंद्रेई साखारोव सोवियत हाइड्रोजन-बम कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिकों में थे, पर बाद में मानवाधिकार और शांतिपूर्ण असहमति के प्रतीक बने — 1975 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उनके नाम का यह पुरस्कार अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता और विचार-स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों को यूरोपीय संसद का सर्वोच्च मानवाधिकार-सम्मान देता है। ICC का चयन इस वर्ष विशेष संदर्भ रखता है: 2025 से अदालत के अभियोजकों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं (विशेषकर अमेरिका द्वारा) — विज्ञप्ति में इन्हें अंतरराष्ट्रीय न्याय-तंत्र पर दबाव के रूप में चित्रित किया गया है। EU की ‘अवरोधक संरचना’ (blocking statute) एक ऐसा कानून है जो तीसरे देश के कानूनों का प्रभाव EU-क्षेत्र में निष्प्रभावी करता है; इसे सक्रिय करने की माँग का अर्थ है कि यूरोपीय संस्थान ICC के साथ काम करने वाले यूरोपीय निकायों को बाहरी प्रतिबंधों से बचाना चाहते हैं। ‘अंतिम उपाय की अदालत’ का सिद्धांत — पूरकता (complementarity) — ICC की क्षेत्राधिकार-संरचना का मूल है: राष्ट्रीय अदालतें पहले कार्रवाई करें, अदालत तभी हस्तक्षेप करे जब वे अनिच्छुक या असमर्थ हों।

PCSMANTRA.COM

परीक्षा की दृष्टि से

पुरस्कार का वर्ष-स्थापना (1988), नामकर्ता (आंद्रेई साखारोव), देने वाली संस्था (यूरोपीय संसद), 2026 विजेता (ICC और अधिकारी), रोम सन्तियमाला और दिसंबर स्ट्रासबर्ग समारोह — प्रिलिम्स तथ्य।

स्रोत और सीमाएँ

- यूरोपीय संसद प्रेस-विज्ञप्ति, 22 अक्टूबर 2026 (पढ़ी): europarl.europa.eu प्रेस-विज्ञप्ति
- **सीमाएँ:** पुरस्कार-राशि इस खुले स्रोत में नहीं थी, इसलिए नहीं लिखी गई। समारोह दिसंबर 2026 में होना है; विवरण विज्ञप्ति-आधारित।

PCSMANTRA.COM